



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 34 पटना, बुधवार, 2 भाद्र 1944 (श0)
24 अगस्त 2022 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-15
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेशों के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	16-16
पुरक	---
पुरक-क	17-25

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचनाएं

18 जुलाई 2022

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-01/2022-3630—सुश्री स्वीटी सुमन, जिला अवर निबंधक, शेखपुरा के विरुद्ध जमीन का निबंधन हेतु बाह्य व्यक्ति के द्वारा नाजायज राशि की मांग करना, सी0सी0टी0वी0 कैमरा का रिकॉर्ड नहीं दिखाना, दस्तावेज लंबित रखना, निबंधन अधिनियम, निबंधन नियमावली एवं अन्य संगत निदेशों का उल्लंघन करना आदि आरोप के लिए विभागीय संकल्प सं-2078 दिनांक-18.04.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक-236 दिनांक-24.05.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें निष्कर्षित किया गया है कि आरोप सं0-02 आंशिक (रेफर दस्तावेज के प्रेषण में हुये बिलंब, आगत-निर्गत पंजी में प्रविष्टियों को छोड़ना एवं विभिन्न कारणों से दस्तावेज को लंबित रखने से संबंधित आरोप) आंशिक रूप से प्रमाणित होता है। परंतु आरोपी पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर उनके द्वारा दायित्वों का निर्वाहण किया गया है। इस कारण दस्तावेज के प्रेषण में हुये बिलंब एवं पंजियों को अद्यतन नहीं रखने में संबंधित लिपिक पूर्ण रूपेण उत्तरदायी हैं। फिर भी कार्यालय प्रधान होने के कारण जिला अवर निबंधक, शेखपुरा सुश्री स्वीटी सुमन में पर्यवेक्षण एवं कार्यालय कर्मियों पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव पाया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-2874 दिनांक-08.06.2022 द्वारा प्रमाणित आरोपो पर आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी है। जिला अवर निबंधक, शेखपुरा के पत्रांक-395 दिनांक-22.06.2022 द्वारा द्वितीय बचाव वयान विभाग में समर्पित किया गया है।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या-02 को आंशिक रूप से प्रमाणित किया गया है। आरोपी पदाधिकारी को ससमय सी0सी0टी0वी0 कैमरा को ऑपरेट करने हेतु तकनीशियन उपलब्ध कराना चाहिए था, क्योंकि यह जाँच पूर्व से निर्धारित थी एवं इसकी सूचना आरोपी पदाधिकारी को संज्ञान में था। जाँच में पाया गया है कि आलोच्य नाजायज राशि की मांग जिला अवर निबंधन कार्यालय में श्री अंजनी कुमार नामक बाह्य व्यक्ति द्वारा की गई थी एवं बाह्य व्यक्ति को बिचौलियों के तौर पर प्रश्रय एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरे से परिवाद के आरोप का सत्यापन बाधित करने के उद्देश्य से कैमरे के ऑपरेटर को उपस्थित नहीं कराना आरोपी पदाधिकारी के कार्यकलाप को संदिग्ध करता है।

आरोप सं0-3, रेफर दस्तावेज के प्रेषण में हुये विलंब, आगत-निर्गत पंजी में प्रविष्टियों को छोड़ना एवं विभिन्न कारणों से दस्तावेज को लंबित रखने से संबंधित आरोप प्रमाणित होता है। हालाँकि दस्तावेज के प्रेषण में हुये विलंब एवं पंजियों को अद्यतन नहीं रखने में संबंधित लिपिक पूर्ण रूपेण उत्तरदायी हैं। फिर भी कार्यालय प्रधान होने के कारण जिला अवर निबंधक, शेखपुरा सुश्री स्वीटी सुमन में पर्यवेक्षण एवं कार्यालय कर्मियों पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव पाया गया है। अतएव आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय बचाव वयान स्वीकार योग्य नहीं है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं सुश्री स्वीटी सुमन से प्राप्त द्वितीय बचाव वयान पर सम्यक् विचारापरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(1) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
निरंजन कुमार, उप-सचिव।

27 जुलाई 2022

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-95/2021-3770—श्री संजय कुमार, तत्का0 जिला अवर निबंधक, सारण सम्प्रति जिला अवर निबंधक, मधेपुरा के विरुद्ध टोप्पो लैण्ड/असर्वेक्षित भूमि के निबंधन पर लगाए गए रोक के अवहेलना करते हुए C.W.J.C. No.2524/2018 राकेश गुप्ता बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में वादी राकेश गुप्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सं0-4102 का निबंधन दिनांक 10.05.2019 को किया गया है। Grounds of Appeal जिला विधि शाखा से अनुमोदन कराने के पश्चात् एल0पी0ए0 दायर करने में अभिरुचि नहीं लेने, माननीय न्यायालय में एल0पी0ए0 दायर करने में काफी बिलम्ब होने के कारण श्री कुमार का उक्त आचरण कार्य के प्रति लापरवाही एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करने आदि आरोप में विभागीय संकल्प सं0-1190 दिनांक 24.02.22 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमंडल, पटना के गै0स0प्रे0सं0 -343 दिनांक 11.04.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आरोप सं0-1 विभागीय मार्गदर्शन एवं सरकार/विभाग द्वारा टोपो लैण्ड/असर्वेक्षित भूमि के निबंधन पर लगाए गए रोक के अवहलना करते हुए C.W.J.C No.2524/2018 राकेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में वादी राकेश गुप्ता द्वारा टोपो लैण्ड/असर्वेक्षित भूमि के निबंधन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज सं0-4102 का निबंधन दिनांक 10.05.2019 को किया गया है, को प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 के तहत संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक-2087 दिनांक 19.04.2022 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी है।

4. श्री कुमार, जिला अवर निबंधक, मधेपुरा के पत्रांक-511 दिनांक 28.05.2022 द्वारा अपना बचाव वयान विभाग में समर्पित किया गया है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा बचाव वयान में कहा गया है कि जिला प्रशासन को माननीय न्यायालय के आदेश से अवगत कराया गया था। निबंधन विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निदेश प्राप्त हुआ था। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के पत्रांक-1684 दिनांक-08.05.2019 द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक-10.05.19 को एकररनामा दस्तावेज का निबंधन किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेश के आलोक में अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई किए जाने के संबंध में विशेष अभिरुचि नहीं ली गई, इस प्रकार विभागीय निदेश के अनुपालन में शिथिलता बरती गई है, सही नहीं है।

5. जमीन की खरीद-बिक्री के लिये एकररनामा का निबंधन जिला अवर निबंधक, सारण द्वारा किया गया था। इसके पश्चात् बिक्रय पत्र का निबंधन किये जाने से इनकार करने पर कानूनी उलझन उत्पन्न होने की पूरी संभावना थी जबकि एकररनामा का निबंधन के दौरान जिला अवर निबंधक को जमीन की प्रकृति की निश्चित रूप से जानकारी होगी। अतएव एकररनामा का निबंधन किया जाना ही उचित नहीं था। सी0 डब्लू0 जे0 सी0 नं0-2524/2018 में दिनांक 19.04.2019 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध अपील की गुजांश भी बनती थी। सी0 डब्लू0 जे0 सी0 नं0-2524/2018 में दिनांक-19.04.2019 को पारित आदेश से असंतुष्ट होने की स्थिति में त्वरित अपील दायर करने की कार्रवाई किया जाना चाहिए था। अतएव आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय बचाव वयान तार्किक एवं तथ्य परक नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव वयान के समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 (vi) के तहत 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धियों संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-3282 दिनांक 24.06.2022 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अभिमत की मांग की गयी है। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-1398 दिनांक 20.07.2022 द्वारा दिनांक 13.07.2022 को आहूत आयोग की पूर्ण बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त किया गया है। अतः श्री संजय कुमार, तत्का0 जिला अवर निबंधक, सारण सम्प्रति-जिला अवर निबंधक, मधेपुरा के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 (vi) के तहत 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धियों संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दंड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

28 जुलाई 2022

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-27/2019-3785-सुश्री अपर्णा शिवा, तत्का0 अवर निबंधक, दानापुर (पटना) सम्प्रति अवर निबंधक, हवेली, खड़गपुर (मुंगेर) के विरुद्ध श्री इम्तेयाज अहमद खान, पिता-नइमउल्लाह खान, जुनैदपुर, थाना-दानापुर, जिला पटना से प्राप्त परिवाद पत्र जिसमें मो0 इकबाल अहमद खान, पिता-स्व0 मो0 नइमउल्लाह खान, जुनैदपुर, थाना-दानापुर, जिला- पटना ने उनके पक्ष में एक वसियतनामा दस्तावेज घर पर आकर निबंधित करने का अनुरोध किया था, जिसका निष्पादन नहीं किया गया, जबकि घर पर आकर निबंधन करने का फीस J (I) का भुगतान E-Stamp के माध्यम से दिनांक 04.02.2019 को कर दिया गया था। जॉचोपरान्त पाया गया है कि कमीशन बही पर उक्त तिथि को प्राप्त संबंधित कमीशन के आवेदन की प्रविष्टि भी नहीं की गयी है तथा एक अन्य परिवादी श्री रामगुलाम यादव द्वारा (i) दस्तावेजों को Pending करके निबंधन करना (ii) स्थल निरीक्षण के नाम पर शोषण करना (iii) दस्तावेजों का परिदान (iv) दस्तावेजों पर निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर (v) आम जनता से अमानवीय व्यवहार (vi) मनमाने तरीके से दस्तावेजों का निबंधन (vii) निबंधन अधिनियमों एवं सरकारी निदेशों की जानकारी नहीं होना (viii) राजस्व वसूली में पिछड़ापन के संबंध में आरोप प्रतिवेदित किया गया है, जिसकी जॉच विभाग में गठित त्रिसदस्यीय समिति से करायी गयी है। त्रिसदस्यीय समिति द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि की गयी है। दस्तावेज सं0-2134/2019 एवं 2147/2019 में रु. 1,16,644/- (एक लाख सोलह हजार छः सौ चौवालीस) रुपये मात्र की राजस्व क्षति हुई है। दस्तावेज के निबंधन में निबंधन अधिनियम 1908 एवं बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2008 के नियम-9 का पालन नहीं किये जाने, विभागीय अधिनियमों/नियमों एवं

बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1) आदि आरोप में विभागीय संकल्प सं0-2505 दिनांक 26.07.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी है।

2. संचालन पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक-38 दिनांक 21.01.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आरोप सं0-1, आरोप सं0-2 (i), (ii) तथा (iii) आंशिक रूप से प्रमाणित, आरोप सं0-2 (v),(vi) प्रमाणित। शेष दो निबंधित दस्तावेजों में आरोपी पदाधिकारी द्वारा जॉच दल को अपेक्षित सहयोग नहीं दिए जाने के कारण आंशिक रूप से प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 के तहत संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक-609 दिनांक 31.01.2022 द्वारा सुश्री शिवा से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी है।

4. सुश्री अपर्णा शिवा, तत्का0 अवर निबंधक, दानापुर सम्प्रति अवर निबंधक, हवेली, खड़गपुर (मुंगेर) के पत्रांक-46 दिनांक 25.02.2022 द्वारा अपना बचाव वयान विभाग में समर्पित किया गया।

सुश्री अपर्णा शिवा, तत्का0 अवर निबंधक, दानापुर सम्प्रति अवर निबंधक, हवेली, खड़गपुर (मुंगेर) से प्राप्त द्वितीय बचाव वयान की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि (1) कमीशन हेतु निबंधन RTPS के अधीन नहीं है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि RTPS से भिन्न मामलों का निष्पादन ही नहीं किया जाय। प्रश्नगत कमीशन का आवेदन अवर निबंधक के संज्ञान में था जिसका उन्होंने स्वीकार किया है किन्तु निबंधन हेतु संबंधित सहायक को उपस्थापित करने का उनके द्वारा निदेश देने का उनके बचाव वयान में नहीं है। यदि संबंधित लिपिक उपस्थापित नहीं किया तो कार्यालय प्रधान के नाते उनका दायित्व था कि उसे निदेशित करते या दण्डात्मक कार्रवाई करते। संचालन पदाधिकारी द्वारा की गयी जॉच में यह आरोप साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित पाया गया है। जॉच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों को अपने द्वितीय बचाव वयान में साक्ष्य आधारित कथन प्रस्तुत नहीं किया गया है। आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय बचाव वयान तार्किक, तथ्य परक एवं साक्ष्य आधारित नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वितीय बचाव वयान के समीक्षोपरांत के तहत 03 (तीन) वेतनवृद्धियों संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने के दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-2422 दिनांक 11.05.2022 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अभिमत की मांग की गयी है। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-1393 दिनांक 20.07.2022 द्वारा दिनांक 13.07.2022 को आहूत आयोग की पूर्ण बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त किया गया है। अतः सुश्री अपर्णा शिवा, तत्का0 अवर निबंधक, दानापुर सम्प्रति अवर निबंधक, हवेली, खड़गपुर (मुंगेर) के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 (vi) के तहत 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धियों संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दंड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

16 अगस्त 2022

सं0 8/आ0 (राज0 उ0)-2-03/2022/4075-श्री प्रमोदित नारायण सिंह, तत्कालीन अधीक्षक मद्य निषेध, समस्तीपुर सम्प्रति अररिया के विरुद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति, विभागीय आदेश की अवहेलना, मद्य निषेध नीति के कार्यान्वयन में लापरवाही एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के उल्लंघन आदि के आरोप में संकल्प सं0-2770 दिनांक-01.06.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी संयुक्त आयुक्त मद्य निषेध द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सिंह Back Pain एवं Neck Pain से ग्रसित थे, उनको चलने-फिरने में कठिनाई हो रही थी, जिसके चलते उनको Bed Rest करना आवश्यक था। उन्हें Bed Rest के साथ-साथ फिजियोथेरेपी कराने का परामर्श चिकित्सक द्वारा दिया गया था। श्री सिंह का अपने कार्य से अनुपस्थिति परिस्थितिजन्य है तथा उनके द्वारा कोई आदेशोपलंघन का मामला नहीं पाया गया है।

3. पूर्व में विभागीय पत्रांक-584 दिनांक-28.01.2022 द्वारा यह निदेशित है कि अधीक्षक मद्य निषेध द्वारा अवकाश में जाने के पूर्व संबंधित जिला पदाधिकारी की अनुमति के पश्चात् आयुक्त उत्पाद की पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक है, परन्तु अभिलेखों से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी के अवकाश में जाने के पूर्व आयुक्त उत्पाद से पूर्वानुमति नहीं ली गयी थी।

6. अतः प्रमोदित नारायण सिंह, तत्कालीन अधीक्षक मद्य निषेध, समस्तीपुर सम्प्रति अररिया को भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

16 अगस्त 2022

सं० 8/आ० (राज० उ०)—2-04/2022/4074—श्री गणेश प्रसाद, अधीक्षक मद्य निषेध, मधुबनी के विरुद्ध जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में ड्रोन को प्रभावी रूप से उपयोग नहीं किये जाने और न ही ब्रेथ एनालाईजर से अधिकाधिक संख्या में व्यक्तियों की जाँच करने के लिए मद्य निषेध नीति की कार्यान्वयन में लापरवाही का आरोप गठित किया गया।

2. श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक—3533 दिनांक—11.07.2022 के द्वारा गठित आरोप के आलोक में बचाव वयान की मांग की गयी।

श्री प्रसाद द्वारा समर्पित बचाव वयान में कहा गया है कि मधुबनी जिला को 03 ड्रोन उपलब्ध कराया गया है जिसमें 01 ड्रोन मद्य निषेध विभाग को और 02 ड्रोन पुलिस विभाग को उपलब्ध कराया गया है। 01 ड्रोन के बावजूद भी पुलिस से अच्छा प्रदर्शन किया गया है। ड्रोन के साथ मात्र दो बैट्री उपलब्ध कराया गया है जिसकी क्षमता अधिकतम 40 मिनट है एवं ड्रोन में लगा नाईट विजन कैमरा नहीं होने के कारण रात्रि में ड्रोन के द्वारा छापामारी/गस्ती संभव नहीं हो पा रही थी, इस समस्या से अवगत कराया गया है। ब्रेथ एनालाईजर से जाँच के संबंध में उल्लेखित किया गया है कि उपलब्ध कराये गये मशीन से व्यक्तियों के स्वांस परीक्षण में काफी समय लग रहा है, जिसके कारण अधिक व्यक्तियों का जाँच संभव नहीं हो पा रहा है।

3. जिला पदाधिकारी के पत्रांक—1158 दिनांक—11.04.2022 में प्रतिवेदित है कि दिनांक—11.03.2022 से 17.03.2022 तक होली त्यौहार 2022 के पूर्ववर्ती एक सप्ताह में उपलब्ध कराया गया प्रतिवेदन की तुलनात्मक समीक्षा में यह पाया गया है कि ड्रोन से की गयी निगरानी एवं ब्रेथ एनालाईजर से व्यक्तियों के किये गये जाँच काफी कम है। जबकि मद्य निषेध के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बार—बार निदेशित किया गया है कि ड्रोन से निगरानी कर अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाया जाय। साथ ही ब्रेथ एनालाईजर का प्रयोग कर व्यक्तियों की जाँच की जाय। प्रस्तुत आँकड़ों से स्पष्ट है कि ड्रोन एवं ब्रेथ एनालाईजर का प्रभावी उपयोग नहीं किया गया है। यह मद्य निषेध के कार्यान्वयन में लापरवाही को प्रदर्शित करता है। अतएव श्री प्रसाद का बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है।

4. सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक—8237 दिनांक—06.07.2017 के द्वारा मार्गदर्शन है कि आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विभागीय कार्यवाही उन्हीं मामलों प्रारंभ किया जाय, जिसमें अनुशासनिक प्राधिकार की राय में आरोपित सरकारी सेवक को वृहद दण्ड दिये जाने की संभावना हो। श्री प्रसाद के विरुद्ध गठित आरोप गंभीर प्रकृति का नहीं है।

5. अतः श्री गणेश प्रसाद, अधीक्षक मद्य निषेध, मधुबनी के विरुद्ध गठित आरोप के आलोक एवं उनके बचाव—बयान पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथासंशोधित के नियम—14 (i) के तहत आरोप वर्ष 2022—23 के लिये निन्दन का दंड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

मृह विभाग (आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं
4 जनवरी 2022

सं० 1/पी1—02/2013 खण्ड—II गृ०आ०—57—श्री अमित रंजन, भा०पु०से० (2018), सहायक पुलिस अधीक्षक, नगर, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सहायक पुलिस अधीक्षक, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

29 जून 2022

सं० 1/एल०1—10—03/2019—गृ०आ०—6325—श्री गणेश कुमार, भा०पु०से० (2000), पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम—10, 11 एवं 20 के अंतर्गत दिनांक 17.06.2022 से 22.06.2022 तक कुल 06 (छः) दिनों के उपाजित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार के उक्त अवकाश अवधि में उनके दैनिक कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में पुलिस उप—महानिरीक्षक (कार्मिक), बिहार, पटना को रहने की घटनोत्तर अनुमति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

18 जुलाई 2022

सं० 1/एल०1-10-09/2022-गृ०आ०-7075—विभागीय अधिसूचना संख्या-3405, दिनांक- 01.04.2022 द्वारा श्रीमती बीणा कुमारी, भा०पु०से०, समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-04, डुमराँव, बक्सर को अखिल भारतीय सेवाएँ (अवकाश) नियमावली 1955 के नियम 18 (D) के अन्तर्गत दिनांक 27.03.2022 से 05.05.2022 तक कुल 40 (चालीस) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. श्रीमती बीणा कुमारी द्वारा उक्त स्वीकृत 40 दिनों के अवकाश को दिनांक-05.04.2022 से 14.05.2022 तक की अवधि में उपभोग किया गया है।

3. तदनुसार श्रीमती बीणा कुमारी द्वारा उपभोग किये गये उक्त स्वीकृत 40 दिनों के अवकाश को दिनांक-05.04.2022 से 14.05.2022 तक की अवधि के रूप में संशोधित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

23 जून 2022

सं० 1/एल०1-10-10/2013-गृ०आ०-6104—श्रीमती निताशा गुड्डिया, भा०पु०से० (2008), पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह-उप-निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को आवश्यक कार्यवश अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अंतर्गत दिनांक 24.06.2022 से 14.07.2022 तक कुल-21 (इक्कीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती निताशा गुड्डिया, भा०पु०से० (2008), के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के दैनिक कार्यों के प्रभार में श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, भा०पु०से० (2010), सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर, रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

6 जुलाई 2022

सं० 1/एल०1-10-10/2015-गृ०आ०-6664—श्री अजिताभ कुमार, भा०पु०से० (1997), अपर पुलिस महानिदेशक (प्रोविजनिंग), बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-5052, दिनांक-25.05.2022 द्वारा दिनांक-26.05.2022 से 19.06.2022 तक कुल-25 दिनों के स्वीकृत उपार्जित अवकाश में से दिनांक-15.06.2022 से 19.06.2022 तक 05 दिनों के उपार्जित अवकाश को रद्द किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

23 जून 2022

सं० 1/एल०1-10-10/2015-गृ०आ०-6103—श्री सत्यवीर सिंह, भा०पु०से० (2008), पुलिस उप-महानिरीक्षक, बेगूसराय क्षेत्र, बेगूसराय को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अंतर्गत दिनांक-24.06.2022 से 10.07.2022 तक कुल 17 (सत्रह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री सत्यवीर सिंह, भा०पु०से० (2008), के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस उप-महानिरीक्षक, बेगूसराय क्षेत्र, बेगूसराय के अतिरिक्त प्रभार में श्री संजय कुमार, भा०पु०से० (2008), पुलिस उप-महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर, रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

13 मई 2022

सं० 1/एल०1-10-16/2009-गृ०आ०-4670—श्रीमती एस० प्रेमलता, भा०पु०से० (2006), तत्कालीन पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह-उप महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, पटना सम्प्रति पुलिस उप-महानिरीक्षक, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11, 12, 13 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 15.07.2021 को 01 (एक) दिन का उपार्जित अवकाश तथा दिनांक 16.07.2021 से 30.07.2021 तक 15 दिनों का रूपांतरित-सह-चिकित्सीय अवकाश (15 x 2 = 30 दिनों के अर्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

6 जुलाई 2022

सं० 1/एल०1-10-19/2017-गृ०आ०-6665—श्री नीलेश कुमार, भा०पु०से० (2010), पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू०), बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-6051, दिनांक-22.06.2022 द्वारा दिनांक-10.06.2022 से

17.06.2022 तक कुल-08 दिनों के स्वीकृत उपार्जित अवकाश में से दिनांक-15.06.2022 से 17.06.2022 तक 03 दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश को रद्द किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

22 जून 2022

सं० 1/एल०1-10-19/2017-गृ०आ०-6051—श्री नीलेश कुमार, भा०पु०से० (2010), पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू), बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अंतर्गत अपने आँख का ईलाज कराने हेतु शंकर नेत्रालय, कोलकाता जाने के लिए दिनांक 10.06.2022 से 17.06.2022 तक कुल 08 (आठ) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार के उक्त अवकाश में उनके कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना को रहने की घटनोत्तर अनुमति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

3 मार्च 2022

सं० 1/पी०1-01/2016 गृ०आ०-2105—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री राकेश कुमार सिन्हा, भा०पु०से० (2012)	पुलिस अधीक्षक (बी०), विशेष शाखा, बिहार, पटना	पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना
2.	श्री अभय कुमार लाल, भा०पु०से० (2010)	पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना	पुलिस अधीक्षक (बी०), विशेष शाखा, बिहार, पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

2 फरवरी 2022

सं० 1/पी०1-01/2020 गृ०आ०-858—बिहार पुलिस मुख्यालय (कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग) का आदेश पत्र सं०-एक्स०पी०-02-03-01-2021/95 दिनांक-14.01.2022 द्वारा गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के अनुमोदन की प्रत्याशा में 73 RR वर्ष 2019 बैच के 02 (दो) एवं 2020 बैच के 03 (तीन) कुल-05 (पाँच) भारतीय पुलिस सेवा के परीक्ष्यमान पदाधिकारियों को बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत जिला व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु उनके नाम के सामने कॉलम-4 में निम्नवत् जिला आवंटित किया गया है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/बैच	गृह जिला/राज्य	जिला व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु आवंटित जिला
1	2	3	4
1.	श्री शुभांक मिश्रा, भा०पु०से० (2019)	कानपुर/उत्तर प्रदेश	वैशाली
2.	श्री के० रामदास, भा०पु०से० (2019)	कृष्णागिरी/तमिलनाडु	रोहतास
3.	सुश्री स्वीटी सहरावत, भा०पु०से० (2020)	रोहिणी/दिल्ली	गया
4.	श्री शरथ आर०एस०, भा०पु०से० (2020)	तिरुवनंतपुरम/केरल	मुजफ्फरपुर
5.	श्री विक्रम सिहाग, भा०पु०से० (2020)	सिकर/राजस्थान	दरभंगा

2. बिहार पुलिस मुख्यालय (कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग) द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के उक्त परीक्ष्यमान पदाधिकारियों का जिला व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु जिला आवंटन की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

24 जनवरी 2022

सं० 1/पी1-02/2013 खण्ड-I गृ०आ०-583—श्री विकास कुमार, भा०पु०से० (2008), पुलिस उप महानिरीक्षक—सह—उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना को अगले आदेश तक निदेशक—सह—राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

24 जनवरी 2022

सं० 1/पी1-02/2013 खण्ड-II गृ०आ०-582—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है/अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/बैच	वर्तमान पदस्थापन	नवपदस्थापन/अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1.	श्री नवीन चन्द्र झा, भा०पु०से० (2009)	पुलिस अधीक्षक पदस्थापन की प्रतीक्षा में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना	समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-09, जमालपुर
2.	श्री पुष्कर आनन्द, भा०पु०से० (2009)	समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-16, पटना	अतिरिक्त प्रभार— समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-14, पटना
3.	श्री अनिल कुमार, भा०पु०से० (2010)	पुलिस अधीक्षक, वितंतु, बिहार, पटना।	पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना।
4.	श्रीमती बीणा कुमारी, भा०पु०से०	पुलिस अधीक्षक, (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना	समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-04, डुमराँव अतिरिक्त प्रभार— समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-18, डुमराँव।
5.	श्री शैशव यादव, भा०पु०से०	अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना (नव प्रोन्नत भा०पु०से०)	समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-13, दरभंगा।
6.	श्री विद्या सागर, भा०पु०से०	पुलिस उपाधीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-10, पटना (नव प्रोन्नत भा०पु०से०)	पुलिस अधीक्षक, वितंतु, बिहार, पटना।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

2 फरवरी 2022

सं० 1/पी1-02/2013 खण्ड-II गृ०आ०-865—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री अमित लोढा, भा०पु०से० (1998)	पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया	पदस्थापन की प्रतीक्षा में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना
2.	श्री विनय कुमार, भा०पु०से० (2004)	पुलिस महानिरीक्षक, (मुख्यालय), बिहार, पटना	पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया
3.	श्रीमती हरप्रीत कौर, भा०पु०से० (2009)	समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-05, पटना अतिरिक्त प्रभार—	वरीय पुलिस अधीक्षक, गया

		समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-10, पटना	
4.	श्री आदित्य कुमार, भा0पु0से0 (2011)	वरीय पुलिस अधीक्षक, गया	पदस्थापन की प्रतीक्षा में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

21 फरवरी 2022

सं0 1/पी1-02/2013 खण्ड-II गृ0आ0-1593—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है/अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है :-

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन/अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1.	श्री गणेश कुमार, भा0पु0से0 (2000)	पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएँ एवं वित्तु, बिहार, पटना	पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार— पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएँ एवं वित्तु, बिहार, पटना
2.	श्री राजीव रंजन, भा0पु0से0 (2005)	पुलिस उप-महानिरीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना	अतिरिक्त प्रभार— पुलिस उप-महानिरीक्षक, रेल, बिहार, पटना
3.	श्री राशिद जर्माँ, भा0पु0से0 (2010)	पुलिस अधीक्षक (जी0), विशेष शाखा, बिहार, पटना	अतिरिक्त प्रभार— पुलिस अधीक्षक (कमजोर वर्ग एवं महिला कोषांग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना
4.	श्री विजय प्रसाद, भा0पु0से0 (2012)	पुलिस अधीक्षक-सह-सहायक निदेशक, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना	अतिरिक्त प्रभार— समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-10, पटना
5.	श्री रमण कुमार चौधरी, भा0पु0से0 (2012)	सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण), बिहार, पटना	अतिरिक्त प्रभार— समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-05, पटना
6.	श्री सुशील कुमार, भा0पु0से0 (2012)	समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-03, बोधगया अतिरिक्त प्रभार— समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-17, बोधगया	पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना
7.	श्री राकेश कुमार, भा0पु0से0 (2013)	नगर पुलिस अधीक्षक, गया	अतिरिक्त प्रभार— समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-03, बोधगया एवं समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-17, बोधगया

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

18 मार्च 2022

सं0 1/पी1-02/2013 खण्ड-II गृ0आ0-2898—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री सैयद इमरान मसूद, भा०पु०से० (2018)	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर, पटना	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लखीसराय।
2.	श्री अभिनव धिमन, भा०पु०से० (2019),	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरंराज, मोतिहारी।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर, पटना।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

5 मई 2022

सं० 1/पी1-02/2013 खण्ड-II गृ०आ०-4468—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1	श्री अमित लोढा भा०पु०से० (1998)	पुलिस महानिरीक्षक (पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	पुलिस महानिरीक्षक, एस०सी०आर०बी०, बिहार, पटना
2	श्री सुनील कुमार भा०पु०से० (2004)	पुलिस उप महानिरीक्षक (सुरक्षा) विशेष शाखा, बिहार, पटना (नव प्रोन्नत पुलिस महानिरीक्षक)	पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना
3	श्री नवल किशोर, भा०पु०से० (2005)	पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना	पुलिस उप महानिरीक्षक एस०सी०आर०बी०, बिहार, पटना (पुलिस अधीक्षक, एस०सी०आर०बी० के पद को पुलिस उप महानिरीक्षक कोटि में उत्कृष्टित करते हुए)
4	श्री मनोज कुमार भा०पु०से० (2008)	पुलिस उप महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, केन्द्रीय मंडल, पटना	पुलिस उप महानिरीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा, बिहार, पटना
5	श्री विवेकानन्द, भा०पु०से० (2008)	सहायक पुलिस महानिरीक्षक (क्यू) बिहार, पटना (नव प्रोन्नत पुलिस उप महानिरीक्षक)	पुलिस उप महानिरीक्षक, पूर्वीय क्षेत्र, भागलपुर
6	श्री नीलेश कुमार भा०पु०से० (2010)	पुलिस अधीक्षक (प्रशिक्षण), विशेष कार्यबल, बिहार, पटना	सहायक पुलिस महानिरीक्षक(क्यू), बिहार, पटना
7	श्री आदित्य कुमार, भा०पु०से० (2011)	पुलिस अधीक्षक, (पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	सहायक पुलिस महानिरीक्षक (निरीक्षण), बिहार, पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

16 मई 2022

सं० 1/पी1-02/2013 खण्ड-II गृ०आ०-4718—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है / अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन/अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1.	सुश्री धुरत सायली सावलाराम, भा०पु०से० (2010)	पदस्थापन की प्रतीक्षा में, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना	समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-05, पटना

2.	श्री संजय कुमार सिंह, भा0पु0से0 (2012)	पुलिस अधीक्षक, मद्यनिषेध, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना	पुलिस अधीक्षक, भोजपुर अतिरिक्त प्रभार— समादेष्टा, अश्वारोही विशेष सशस्त्र पुलिस, आरा
3.	श्री विनय तिवारी, भा0पु0से0 (2015)	पुलिस अधीक्षक, भोजपुर अतिरिक्त प्रभार— समादेष्टा, अश्वारोही विशेष सशस्त्र पुलिस, आरा	पुलिस अधीक्षक, मद्यनिषेध, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

27 जुलाई 2022

सं0 1/पी1-04/2019 गृ0 आ0-7523—विभागीय अधिसूचना संख्या-5847 दिनांक 20.07.2019 द्वारा श्री के0 एस0 द्विवेदी, भा0पु0से0 (1984), सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक, बिहार को बिहार पुलिस हस्तक, 1978 खण्ड-III के परिशिष्ट-72 के क्रमांक-4(ii) (क) [विभागीय अधिसूचना सं0-5531, दिनांक 10.07.2019 द्वारा अधिसूचित] के तहत 03 वर्षों के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्वद, बिहार, पटना के पद पर नियुक्त किया गया।

2. अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्वद, बिहार, पटना के पद पर नियुक्त श्री द्विवेदी को दिनांक 21.07.2022 के प्रभाव से अगले 06 (छः) माह के लिए अवधि विस्तार प्रदान किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

31 मई 2022

सं0 1/पी1-02/2013 खण्ड-II गृ0आ0-5283—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है/अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है :-

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन/अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1.	श्री पंकज सिन्हा, भा0पु0से0 (2004)	पुलिस महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर	अतिरिक्त प्रभार— महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (उत्तरी मंडल), मुजफ्फरपुर
2.	श्री क्षत्रनील सिंह, भा0पु0से0 (2005)	पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (उत्तरी मंडल), मुजफ्फरपुर	पुलिस उप-महानिरीक्षक, शाहाबाद क्षेत्र, डिहरी ऑन-सोन
3.	श्री पी0 कन्नन, भा0पु0से0 (2005)	पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना	पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा
4.	श्रीमती गरिमा मलिक, भा0पु0से0 (2006)	पुलिस उप-महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना	अतिरिक्त प्रभार— पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (केन्द्रीय मंडल), पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

18 अगस्त 2022

सं0 ग्रा0वि0-14(पटना)(लोक शि0नि0)- 01/2021-1163031—श्री आनंद प्रकाश, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, खुशरूपुर (पटना) के द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर परिवाद की

सुनवाईयों में अनुपस्थित रहने के आरोप पर समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 622 दिनांक- 09.02.2021 द्वारा आरोप प्रतिवेदित है ।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री प्रकाश से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा “ द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897” की धारा-2 के तहत लॉकडाउन करने का आदेश दिया गया था । तत्पश्चात अन्य राज्य से वापस आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटीन कैम्प संचालन एवं कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति के मद्देनजर नये राशन कार्ड का निर्गमन साथ ही साथ अपने प्रखंड अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग, विधि व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी, पटना द्वारा प्रखंड के नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु निदेश प्राप्त था। जिसके कारण अनन्य संख्या- 428116028022002441 में निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हो सका।

श्री प्रकाश के विरुद्ध समाज कल्याण विभाग से प्रतिवेदित आरोप एवं तत्संबंध में श्री प्रकाश से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत यह पाया गया कि कोविड काल का वह दौर था जिसमें विविध कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सके ।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री आनंद प्रकाश, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, खुशरूपुर (पटना) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजापाकर (वैशाली) को **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 के नियम-3 के तहत ‘चेतावनी (पत्र निर्गत की तिथि से)’ का दंड अधिरोपित किया जाता है।**

आदेश दिया जाता है कि श्री आनंद प्रकाश की चारित्रि पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरुगन डी0, सचिव।

18 अगस्त 2022

सं0 ग्रा0वि0-14(भा0)भा0-02/2015—1162986—श्री उपेन्द्र दास, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंगराचौक, भागलपुर सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, रफीगंज, औरंगाबाद के विरुद्ध भागलपुर समाहरणालय के पत्रांक 16 (प्र0) दिनांक 31.03.2015 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र ‘क’ प्राप्त है। आरोप पत्र में पंचायत समिति द्वारा 13वीं वित्त आयोग के अंतर्गत ली गयी योजनाओं में गलत ढंग से योजना संचालन, गलत अभिकर्ता चयन, गलत तरीके से अभिलेख के संधारण में संलिप्त होने, विभागीय मार्गदर्शिका का उल्लंघन, योजना को विभक्त कर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने, सरकारी राशि के दुर्विनियोग, संदिग्ध भुगतान, कर अपवंचना, प्राक्कलन से कम राशि का व्यय, सरकारी राशि का गबन आदि आरोप धारित है ।

जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर श्री दास से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या- 397224 दिनांक- 25.02.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । विभागीय कार्यवाही संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष प्रतिवेदन में 13वें वित्त आयोग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में वित्तीय अनियमितता का आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया । संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष प्रतिवेदन पर श्री दास का लिखित अभ्यावेदन प्राप्त किया गया ।

आरोप पत्र में धारित आरोप, जिला पदाधिकारी भागलपुर के मंतव्य, संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी के लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री उपेन्द्र दास, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंगराचौक, भागलपुर सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, रफीगंज, औरंगाबाद द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार राशि का व्यय नहीं कर पूर्ण राशि का व्यय सिर्फ चापाकल पर किया गया । जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा भी

स्पष्ट किया गया है कि पहले चापाकल लगाने की योजना स्वीकृत की गयी फिर मनमाने ढंग से बंदरबांट किया गया जो पंचायती राज विभाग के दिशानिर्देशों की घोर उपेक्षा है। चूंकि उपलब्ध राशि का व्यय एक ही योजना में की गयी अतः आर्थिक दुर्विनियोग का आरोप प्रमाणित होता है। श्री उपेन्द्र दास का लिखित अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतएव श्री उपेन्द्र दास, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंगराचौक, भागलपुर सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, रफीगंज, औरंगाबाद के विरुद्ध संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री उपेन्द्र दास की चारित्री/सेवापुस्त में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरुगन डी0, सचिव।

18 अगस्त 2022

सं0 ग्रा0वि0-R-503/26/2022-Section 14- RDD -1162854—मो0 आसिफ, तत्कालीन अधिसूचित ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह- प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, नीमचकबथानी, गया सम्प्रति प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरख, सारण के विरुद्ध विभाग द्वारा गठित आरोप पत्र में विभागीय अधिसूचना संख्या-477842 दिनांक- 30.06.2021 के द्वारा नवपदस्थापित स्थान नीमचकबथानी, गया के पद पर योगदान नहीं करने एवं अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप धारित है।

उक्त आरोप पर मो0 आसिफ से प्राप्त स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनके पिता गंभीर रूप से बीमार और डायलैसिस पर थे जिसकी सूचना जिला पदाधिकारी, गया को उनके मेल आई डी एवं विभागीय मेल पर तथा रजिस्ट्री डाक से दी गयी थी।

मो0 आसिफ के विरुद्ध गठित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि अनुपस्थिति की सूचना उनके द्वारा दी गयी, किन्तु अवकाश स्वीकृत करने एवं अवकाश विस्तार का अनुरोध नहीं किया गया। वे दिनांक- 12.07.2021 से 21.09.2021 तक अनुपस्थित रहे। इस लंबी अवधि की अनुपस्थिति के लिए उनके द्वारा कोई ठोस कारण भी उपलब्ध नहीं कराया गया। पुनः विभागीय अधिसूचना संख्या- 573708 दिनांक- 21.09.2021 द्वारा जब उनका स्थानांतरण मशरख, सारण किया गया तो उन्होंने दिनांक- 22.09.2021 को ही अपना योगदान मशरख, सारण के प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में समर्पित किया जो संदेह उत्पन्न करता है।

अतएव मो0 आसिफ, तत्कालीन अधिसूचित ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, नीमचकबथानी, गया सम्प्रति प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरख, सारण के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुये उनके विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि मो0 आसिफ की चारित्री/सेवापुस्त में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरुगन डी0, सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

16 अगस्त 2022

सं० 6/गो०-34-03/2016(खण्ड-1)-2251/वा०कर-श्री संतोष कुमार, राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), मगध प्रमंडल, गया को अगले आदेश तक वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना में पदस्थापित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार सिन्हा, राज्य-कर अपर आयुक्त-सह-संयुक्त सचिव।

पर्यावरण एवं वन विभाग

सं० वन/पर्या०-08/2012-627 (ई०)/प०व०

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय :-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के अधीन गठित परियोजना निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई (Project Preparation and Monitoring Unit-PPMU) का वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए अवधि विस्तारित करते हुए कुल रुपये 3804000/- (अड़तीस लाख चार हजार रुपये मात्र) की अनुमानित वार्षिक व्यय पर विभिन्न कोटि के आवश्यकता आधारित 05 कोटि के कुल नौ (09) पदों के अवधि विस्तार की स्वीकृति।

दिनांक 22 अगस्त 2022

आदेश :-

स्वीकृत।

2. बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप वित्तीय वर्ष 2022-2027 तक के लिए विस्तृत कार्यक्रम के निर्माण हेतु लिये गये निर्णयानुसार, पर्यावरण एवं वन विभाग की सहभागिता से कृषि रोड मैप वित्तीय वर्ष 2022-2023 से 2026-27 हेतु तैयार की जा रही योजना तथा विभाग के अन्तर्गत वृहत पैमाने पर एतद् संबंधित संचालित योजनाओं के समन्वय हेतु पूर्व गठित PPMU (2012-13) में कुल सृजित 42 पदों के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2012-13 से संविदा आधारित नियुक्त विभिन्न कर्मियों द्वारा कराये गये कार्यों एवं वित्तीय मितव्ययिता के दृष्टिपथ में उक्त सृजित पदों में से आवश्यकता आधारित 05 विभिन्न कोटि के निम्नवत् कुल 09 पदों का पदवार अंकित अनुमानित मासिक एवं वार्षिक व्यय के आलोक में निम्नांकित पदों के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी जा रही है:-

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	मासिक वेतन	मासिक व्यय (3X4)	वार्षिक व्यय
1	2	3	4	5	6
1	परियोजना प्रबंधन पदाधिकारी	1	40000 (मूल मानदेय का 07% वार्षिक वृद्धि)	40000	480000
2	तकनीकी पदाधिकारी (वानिकी)	3	40000 (मूल मानदेय का 07% वार्षिक वृद्धि)	120000	1440000
3	तकनीकी पदाधिकारी (कृषि वानिकी)	2	40000 (मूल मानदेय का 07% वार्षिक वृद्धि)	80000	960000
4	आशुलिपिक	1	बेल्ट्रॉन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर के अनुरूप	27000 (अनुमानित)	324000
5	कम्प्यूटर ऑपरेटर	2	बेल्ट्रॉन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर के अनुरूप	50000 (अनुमानित)	600000
कुल		09		317000	3804000
कुल वार्षिक व्यय (अड़तीस लाख चार हजार रुपये मात्र)					

3. अवधि विस्तारित पदों पर नियुक्त किये जाने संबंधी नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य सेवा शर्तों विभागीय संकल्प ज्ञापांक-364(ई०) दिनांक-28.06.2012 संकल्प संख्या-243 (ई०) दिनांक-28.05.2014 एवं संकल्प संख्या-842 (ई०) दिनांक-10.10.2017 के प्रावधान के अनुरूप रहेगी।

4. **निधि का स्रोत :-** यह व्यय राज्य योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, मांग संख्या-19, उप शीर्ष-0111-जल-जीवन-हरियाली, विपत्र कोड-19-2406011010111, विषय शीर्ष-0111.02.01-मजदूरी मद में उपलब्ध उपबंधित राशि से किया जाएगा।

5. प्रस्ताव में दिनांक-05.08.2022 की बैठक के मद संख्या-13 के रूप में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति (कार्यवाही का अवतरण संचिका के पृ०-154/प०) प्राप्त है।

6. प्रारूप में संचिका के पृ०-155/प० पर दिनांक-11.08.2022 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

No. 932—I, ALOK Kumar Singh R/o C-16, PatrakarNagar, Kankarbagh, Patna-800020, PS-PatrakarNagar, Dist.-Patna declare that earlier my son was known as Sunny but from today onwards he will be known as Sunny Prakash for all future purposes. Affidavit no. 10513 dated 20.07.2022.

ALOK Kumar Singh.

No. 933—I AAKRITI D/o Vidya Bhushan Prasad Karan, R/o 405 Urmila Kunj Apt, Ara Garden, Jagdeopath P.O.-B. V. College, Rupaspur Patna-800014 have changed my name Aakriti to Aakriti Karan for all purposes in future vide affidavit no. 1731 dated 03.02.2022.

AAKRITI.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट का पूरक(अ0) प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० कारा/नि०को०(अधी०)—०१-४१/२०२१—८६७१

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

17 अगस्त 2022

चूँकि बिहार-राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि दिनांक 20.08.2019 को मंडल कारा, सीवान के विचाराधीन बंदी लाल बहादुर प्रसाद, पे०-बलीराम प्रसाद की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हुई मृत्यु की घटना में श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, सासाराम द्वारा बंदी को विलंब से सदर अस्पताल भेजने में गंभीर लापरवाही एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरती गई है।

श्री कुमार का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-218, 796 (i), (ii) एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1), (2) के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, सासाराम के विरुद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

6. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

सं० कारा/नि०को०(अधी०)—०१-२२/२०२२—८६७२

17 अगस्त 2022

श्री रूपक कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना (सम्प्रति निलंबित) संलग्न केन्द्रीय कारा, बक्सर के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में विशेष निगरानी इकाई थाना काण्ड संख्या-05/2022 दिनांक-10.04.2022 धारा-13 (1) (b) एवं धारा-13 (2) r/w 12 of P.C. Act 1988 (यथा-संशोधित) तथा 120 (बी) भा० द० वि० दर्ज किया गया है। श्री रूपक कुमार, तत्कालीन सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना द्वारा ज्ञात वैध स्रोतों से लगभग 1,37,36,854/-रु० (एक करोड़ सैतीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ चौवन रुपये) का प्रत्यानुपातिक धनार्जन किया गया है। श्री कुमार द्वारा कारा सेवा में रहने के दौरान अपने पद का दुरुपयोग कर नाजायज एवं भ्रष्ट तरीके से अपने आय के वैध स्रोतों से अत्यधिक सम्पत्ति न केवल अपने तथा

अपने परिजनों के नाम से अर्जित किया गया है बल्कि इनमें से कई सम्पत्तियों को जानबूझकर अपने सम्पत्ति उद्घोषणा (Declaration of Assets and Liabilities) में छुपाया भी गया है। श्री कुमार का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-3(1) एवं 19(6) के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है तथा एक सरकारी सेवक के रूप में इनके नैतिक कदाचार एवं पद के दुरुपयोग तथा भ्रष्ट आचरण का द्योतक है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री रूपक कुमार, तत्कालीन सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना (सम्प्रति निलंबित) संलग्न केन्द्रीय कारा, बक्सर के विरुद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री संजय कुमार चौधरी, सहायक कारा महानिरीक्षक(क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

6. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

सं० कारा/नि०को०(अधी०)-01-12/2022-8673

17 अगस्त 2022

श्री सुरेश चौधरी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में विशेष निगरानी इकाई थाना काण्ड संख्या-06/2022 दिनांक-04.05.2022 धारा-13 (1) (b) एवं धारा-13 (2) r/w 12 of P.C. Act 1988 (यथा-संशोधित) तथा 120 (बी) भा० द० वि० दर्ज किया गया है। श्री सुरेश चौधरी, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा ज्ञात वैध स्रोतों से लगभग 1,59,07,928/-रु० (एक करोड़ उनसठ लाख सात हजार नौ सौ अठाईस रुपये) का प्रत्यानुपातिक धनार्जन किया गया है। श्री चौधरी द्वारा कारा सेवा में रहने के दौरान अपने पद का दुरुपयोग कर नाजायज एवं भ्रष्ट तरीके से अपने आय के वैध स्रोतों से अत्यधिक सम्पत्ति न केवल अपने तथा अपने परिजनों के नाम से अर्जित किया गया है बल्कि इनमें से कई सम्पत्तियों को जानबूझकर अपने सम्पत्ति उद्घोषणा (Declaration of Assets and Liabilities) में छुपाया भी गया है। श्री चौधरी का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-3(1) एवं 19(6) के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है तथा एक सरकारी सेवक के रूप में इनके नैतिक कदाचार एवं पद के दुरुपयोग तथा भ्रष्ट आचरण का द्योतक है। इसके अतिरिक्त पूर्व में दिनांक 23.10.2021 को जिला प्रशासन, सहरसा द्वारा मंडल कारा, सहरसा में की गई औचक छापेमारी में सजायाफ्ता बंदी आनन्द मोहन, पे०-स्व० सच्चिदानन्द सिंह के कब्जे से 04 मोबाईल फोन, 01 मोबाईल चार्जर एवं विचाराधीन बंदी दीपक कुमार, पे०-दशरथ यादव के कब्जे से 01 मोबाईल फोन तथा वार्ड नं०-3 के पास लावारिस हालत में 01 मोबाईल फोन बरामद किया गया। पुनः दिनांक 16.11.2021 को कारा प्रशासन द्वारा की गई छापेमारी में खैनी, गांजा एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद किया गया। कारा के अन्दर भारी संख्या में मोबाईल एवं अन्य आपत्तिजनक/प्रतिबंधित सामग्रियों का बरामद होना श्री सुरेश चौधरी, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा की अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता एवं पदीय दायित्व के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री सुरेश चौधरी, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) के तहत मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री चौधरी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

6. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

सं० 1/एम02-60-41/2021 गृ०आ०-552

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

21 जनवरी 2022

श्री मो० शफीउल हक, भा०पु०से० (2007) तत्कालीन पुलिस उप-महानिरीक्षक मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जाँच बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना से करायी गयी।

2. और चूँकि आर्थिक अपराध इकाई के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ कि श्री हक द्वारा सहायक अवर पुलिस निरीक्षक, मो० उमरान एवं एक निजी व्यक्ति के माध्यम से मुंगेर क्षेत्रान्तर्गत अधिसंख्य कनीय पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों से अवैध राशि की उगाही का कार्य कराया जा रहा था। जाँच के क्रम में यह भी प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुआ कि वसूली करने वाले सहायक पुलिस अवर निरीक्षक श्री मो० उमरान के गलत कृत्य संज्ञान में होने के बावजूद उनके विरुद्ध कोई निरोधात्मक कार्यवाई नहीं करना इस पूरे घटनाक्रम में श्री हक की सहभागिता को परिलक्षित करता है तथा उन्हें भ्रष्टाचार के पोषक के रूप में स्थापित करता है। फलस्वरूप श्री हक के उपरोक्त संदिग्ध आचरण एवं संबंधित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 8 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया और इसके निमित्त विभागीय ज्ञापन सं० 8825, दिनांक 03.11.2021 के माध्यम से 'आर्टिकल्स ऑफ चार्ज', 'स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेन्स ऑफ मिसबिहेवियर एण्ड मिसकण्डक्ट', साक्ष्य/गवाह सूची सहित निर्गत की गयी।

3. और चूँकि श्री हक के विरुद्ध उक्त आरोपों की गंभीरता को दृष्टिपथ रखते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा श्री हक को निलंबित करने की अनुशंसा की गयी। फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा उक्त आरोपों की गंभीरता एवं प्रकृति पर सम्यक विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(1)(a) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मो० शफीउल हक, भा०पु०से० (2007) को विभागीय संकल्प सं० 9699, दिनांक 01.12.2021 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

4. श्री हक के निलंबन के संबंध में अपेक्षित प्रतिवेदन गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजते हुए उनके निलंबन को संपुष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया। श्री हक के निलंबन को संपुष्ट करने के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक 26011/56/2021-IPS.II, दिनांक 21.12.2021 के माध्यम से अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(1) का संदर्भ उल्लिखित करते हुए संसूचित किया गया कि श्री मो० शफीउल हक दिनांक 01.12.2021 को निलंबित हुए थे, जब कि राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध दिनांक 03.11.2021 को ही आरोप-पत्र जारी करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी थी। उक्त नियम के अंतर्गत गृह मंत्रालय, द्वारा निलंबन को संपुष्ट करने की आवश्यकता तभी होती है जब राज्य सरकार निलंबन से 30 दिन आगे की तिथि तक आरोप-पत्र जारी कर पाने में असमर्थ हो। अतः प्रस्तुत मामले में उक्त नियम के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा अधिकारी के निलंबन को संपुष्ट (confirm) करने की आवश्यकता नहीं है।

5. अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(8)(a) के अद्यतन प्रावधान के अनुसार निलंबन, विस्तारण के पूर्व 60 दिनों तक वैध रहता है और इसका विस्तारण पहली बार अधिकतम 120 दिनों के लिए किया जा सकता है। उक्त प्रावधान एवं भारत सरकार के संदर्भित पत्र के आलोक में श्री हक के निलंबन की अवधि 60 दिनों तक अर्थात् दिनांक 01.12.2021 से 29.01.2022 तक है।

6. श्री हक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के निमित्त विभागीय ज्ञापन सं०-8825 दिनांक 03.11.2021 के माध्यम से निर्गत आरोप पत्र के संदर्भ में उनके द्वारा बचाव बयान समर्पित करने हेतु पत्र दिनांक 25.11.2021 के माध्यम से अतिरिक्त कागजात की मांग की गयी। श्री हक के उक्त पत्र के संबंध में मंतव्य गठित कर उपलब्ध कराने हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार से अनुरोध किया गया है। इसी बीच श्री हक द्वारा पत्र दिनांक 17.12.2021 के माध्यम से बचाव-बयान समर्पित कर दिया गया है। श्री हक के बचाव बयान की समीक्षा की जा रही है। श्री हक के विरुद्ध गठित आरोप एवं इस पर उनके द्वारा समर्पित बचाव-बयान की समीक्षा पर अनुशासनिक प्राधिकार का निर्णय/आदेश प्राप्त करने की कार्यवाई की जानी है। ऐसी स्थिति में श्री मो० शफीउल हक, भा०पु०से० (2007) के निलंबन को बनाये रखने के औचित्य/आधार के संबंध में दिनांक 07.01.2022 को निलंबन समीक्षा समिति द्वारा विचार किया गया और विचारोपरांत समिति द्वारा श्री मो० शफीउल हक, भा०पु०से० (2007) के निलंबन की अवधि दिनांक 29.01.2022 के आगे 120 दिनों तक अर्थात् दिनांक 29.05.2022 तक विस्तारण की अनुषंसा की गयी, जिसे अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

7. अतः अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(8)(a) के तहत श्री मो० शफीउल हक, भा०पु०से० (2007) के निलंबन अवधि दिनांक 29.01.2022 के आगे 120 दिनों तक अर्थात् दिनांक 29.05.2022 तक विस्तारित की जाती है।

8. मो० शफीउल हक, भा०पु०से० (2007) को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० संधिल कुमार, सचिव।

15 जुलाई 2022

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के जाँच प्रतिवेदन एवं उसमें निहित निष्कर्ष तथा पुलिस महानिदेशक, बिहार की अनुशंसा के आलोक में भोजपुर जिला में बालू के अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, इसमें संलग्न लोगों को मदद पहुँचाने, अवैध उत्खनन/परिवहन में संलिप्त रहने, अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखने एवं संदिग्ध आचरण से संबंधित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(1)(a) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राकेश कुमार दूबे, भा०पु०से० (नवप्रोन्नत), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, भोजपुर को विभागीय संकल्प 5102, दिनांक 27.07.2021 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। साथ ही, उक्त गंभीर आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित करने के निमित्त विभागीय ज्ञापन 6293, दिनांक 24.08.2021 द्वारा "आर्टिकल्स ऑफ चार्ज", "स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन्स ऑफ मिसबिहेवियर एण्ड मिसकण्डक्ट", साक्ष्य/गवाह तालिका सहित निर्गत किया गया।

2. और चूँकि अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(1)(a), जिसके तहत श्री दूबे को निलंबित किया गया, के प्रावधानों के आलोक में श्री दूबे के निलंबन की संपुष्टि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक 26011/24/2021-IPS.II, दिनांक 06.08.2021 के फलस्वरूप श्री दूबे के निलंबन की अवधि 60 (साठ) दिनों तक अर्थात् दिनांक 27.07.2021 से 24.09.2021 तक बरकरार थी। श्री दूबे के निलंबन अवधि की समीक्षा हेतु दिनांक 13.09.2021 को आयोजित निलंबन समीक्षा समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में विभागीय संकल्प सं० 7268, दिनांक 20.09.2021 द्वारा दिनांक 24.09.2021 के आगे 120 दिनों तक अर्थात् दिनांक 22.01.2022 तक निलंबन अवधि को विस्तारित किया गया। पुनः दिनांक 07.01.2022 को आयोजित निलंबन समीक्षा समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में विभागीय संकल्प सं० 550, दिनांक 21.01.2022 द्वारा श्री दूबे के निलंबन अवधि को दिनांक 22.01.2022 के आगे 180 दिनों तक अर्थात् दिनांक 21.07.2022 तक विस्तारित किया गया।

3. और चूँकि श्री दूबे के विरुद्ध उक्त गंभीर आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया। इसके निमित्त विभागीय ज्ञापन सं० 6293, दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से "आर्टिकल्स ऑफ चार्ज" एवं "स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन्स ऑफ मिसबिहेवियर एण्ड मिसकण्डक्ट" साक्ष्य/गवाह तालिका सहित निर्गत करते हुए अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 8(5)(a) के तहत 30 दिनों के अंदर बचाव-बयान समर्पित करने हेतु श्री दूबे को अवसर प्रदान किया गया।

उक्त के आलोक में श्री दूबे द्वारा बचाव-बयान समर्पित करने हेतु पत्र दिनांक 11.09.2021 के माध्यम से कतिपय कागजात की माँग की गयी। इस संबंध में उन्हें यह बताये जाने पर कि आरोप पत्र के साथ उपलब्ध कराये गये साक्ष्य/कागजात बचाव-बयान समर्पित करने के लिए पर्याप्त हैं, उनके द्वारा पुनः उन्हीं कागजात को आवश्यक बतलाते हुए पत्र दिनांक 21.10.2021 के माध्यम से माँग की गयी। श्री दूबे के उक्त पत्रों के संदर्भ में बिहार पुलिस मुख्यालय के मंतव्य से श्री दूबे को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा याचित अतिरिक्त कागजात आरोपों के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं और आरोप पत्र के साथ सभी आवश्यक कागजात उपलब्ध करा दिये गये हैं, जो बचाव-बयान समर्पित करने के लिए पर्याप्त हैं। साथ ही, उनको बचाव-बयान समर्पित करने का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 10 दिनों का समय प्रदान किया गया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा उक्त अनुरोध के बावजूद उनके द्वारा बचाव-बयान समर्पित नहीं किया गया। फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 8(6)(b) में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त नियमावली के नियम 8(2) के तहत विभागीय संकल्प सं० 696, दिनांक 27.01.2022 के माध्यम से मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री दूबे द्वारा जाँच पदाधिकारी की नियुक्त होने के उपरांत पत्र दिनांक 04.02.2022 के माध्यम से बचाव-बयान समर्पित किया गया। मुख्य जाँच आयुक्त के समक्ष श्री दूबे द्वारा पुनः अपने पत्र दिनांक 11.09.2021 एवं 21.10.2021 द्वारा याचित कागजात की माँग की गयी। इस संबंध में विभागीय पत्रांक 3472, दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को अवगत कराया गया कि आरोपित पदाधिकारी को पूर्व में विभागीय पत्रांक 10328, दिनांक 21.12.2021 के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 23.05.2022 के माध्यम से अपने आवेदन दिनांक 11.09.2021 द्वारा याचित कागजात की पुनः माँग की गयी। इस संबंध में विभागीय पत्र 5979, दिनांक 20.06.2022 के माध्यम से प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को अवगत कराया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने आवेदन दिनांक 23.05.2022 में किसी नये कागजात की माँग नहीं की गयी है। उनके द्वारा अपने पूर्व के आवेदन दिनांक 11.09.2021 द्वारा याचित कागजात की ही पुनः माँग की गयी है, जिसके संदर्भ में उन्हें पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है। उक्त तथ्य से स्पष्ट होता है कि श्री दूबे द्वारा विभागीय कार्यवाही में सहयोग नहीं किया जा रहा है।

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा श्री राकेश कुमार दूबे, भा०पु०से० (नवप्रोन्नत) के विरुद्ध आय के ज्ञात एवं वैध स्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियाँ अर्जित करने के संबंध में आर्थिक अपराध इकाई, थाना कांड सं० 17/2021, दिनांक 15.09.2021 दर्ज करते हुए विभाग को सूचित किया गया है।

श्री दूबे द्वारा अपने निलंबन को वापस लेने हेतु सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को संबोधित करते हुए अपील अभ्यावेदन राज्य सरकार में समर्पित किया गया। उनके अपील अभ्यावेदन निलंबन की तिथि से छः माह से अधिक अवधि के बाद समर्पित करने एवं विलंब के लिए किसी कारण का उल्लेख नहीं करने के आलोक में उनके अपील अभ्यावेदन को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 21(1)(C) के प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार द्वारा

रोक (withhold) लिया गया। उक्त आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा भी श्री दूबे के अपील अभ्यावेदन को अविचारणीय बताया गया।

4. अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(1C) के तहत भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए निलंबित श्री दूबे को दो वर्ष तक राज्य निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा पर निलंबन में बनाये रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में श्री दूबे के निलंबन को बनाये रखने के औचित्य/आधार के संबंध में दिनांक 01.07.2022 को निलंबन समीक्षा समिति द्वारा विचार किया गया। विचारोपरांत समिति द्वारा श्री दूबे के निलंबन अवधि को दिनांक 21.07.2022 के आगे 180 दिनों तक अर्थात् दिनांक 17.01.2023 तक विस्तारित करने की अनुशंसा की गयी, जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

5. अतः अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(8)(d) के प्रावधानों के अंतर्गत श्री राकेश कुमार दूबे, भा0पु0से0 (नवप्रोन्नत) के निलंबन की अवधि दिनांक 21.07.2022 के आगे 180 दिनों तक अर्थात् दिनांक 17.01.2023 तक विस्तारित किया जाता है।

6. श्री राकेश कुमार दूबे, भा0पु0से0 (नवप्रोन्नत) को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

सं0 1/एम02-60-41/2021 गु0आ0-5027

25 मई 2022

श्री मो0 शफीउल हक, भा0पु0से0 (2007) तत्कालीन पुलिस उप-महानिरीक्षक मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जाँच बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना से करायी गयी। आर्थिक अपराध इकाई के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ कि श्री हक द्वारा सहायक अवर पुलिस निरीक्षक, मो0 उमरान एवं एक निजी व्यक्ति के माध्यम से मुंगेर क्षेत्रान्तर्गत अधिसंख्य कनीय पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों से अवैध राशि की उगाही का कार्य कराया जा रहा था। जाँच के क्रम में यह भी प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुआ कि वसूली करने वाले सहायक पुलिस अवर निरीक्षक श्री मो0 उमरान के गलत कृत्य संज्ञान में होने के बावजूद उनके विरुद्ध कोई निरोधात्मक कार्रवाई नहीं करना इस पूरे घटनाक्रम में श्री हक की सहभागिता को परिलक्षित करता है तथा उन्हें भ्रष्टाचार के पोषक के रूप में स्थापित करता है। फलस्वरूप श्री हक के उपरोक्त संदिग्ध आचरण एवं संबंधित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 8 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया और इसके निमित्त विभागीय ज्ञापन सं0 8825, दिनांक 03.11.2021 के माध्यम से 'आर्टिकल्स ऑफ चार्ज', 'स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेप्स ऑफ मिसबिहेवियर एण्ड मिसकण्डक्ट', साक्ष्य/गवाह सूची सहित निर्गत की गयी।

2. और चूँकि श्री हक के विरुद्ध उक्त आरोपों की गंभीरता को दृष्टिपथ रखते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा श्री हक को निलंबित करने की अनुशंसा की गयी। फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा उक्त आरोपों की गंभीरता एवं प्रकृति पर सम्यक विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(1)(a) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मो0 शफीउल हक, भा0पु0से0 (2007) को विभागीय संकल्प सं0 9699, दिनांक 01.12.2021 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. और चूँकि श्री हक के निलंबन के संबंध में अपेक्षित प्रतिवेदन गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजते हुए उनके निलंबन को संपुष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया। श्री हक के निलंबन को संपुष्ट करने के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक 26011/56/2021-IPS.II, दिनांक 21.12.2021 के माध्यम से अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(1) का संदर्भ उल्लिखित करते हुए संसूचित किया गया कि श्री मो0 शफीउल हक दिनांक 01.12.2021 को निलंबित हुए थे, जब कि राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध दिनांक 03.11.2021 को ही आरोप-पत्र जारी करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी थी। उक्त नियम के अंतर्गत गृह मंत्रालय, द्वारा निलंबन को संपुष्ट करने की आवश्यकता तभी होती है जब राज्य सरकार निलंबन से 30 (तीस) दिन आगे की तिथि तक आरोप-पत्र जारी कर पाने में असमर्थ हो। अतः प्रस्तुत मामले में उक्त नियम के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा अधिकारी के निलंबन को संपुष्ट (confirm) करने की आवश्यकता नहीं है।

4. और चूँकि अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(8)(a) के अद्यतन प्रावधान के अनुसार निलंबन, विस्तारण के पूर्व 60 (साठ) दिनों तक वैध रहता है और इसका विस्तारण पहली बार अधिकतम 120 दिनों के लिए किया जा सकता है। उक्त प्रावधान एवं भारत सरकार के संदर्भित पत्र के आलोक में श्री हक के निलंबन की अवधि 60 (साठ) दिनों तक अर्थात् दिनांक 01.12.2021 से 29.01.2022 तक थी। श्री हक के निलंबन अवधि को उक्त नियमावली के नियम 3(8)(a) के आलोक में दिनांक 29.01.2022 के आगे 120 (एक सौ बीस) दिनों तक अर्थात् दिनांक 29.05.2022 तक विस्तारित करने की अनुशंसा निलंबन समीक्षा समिति द्वारा की गयी। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प सं0 552, दिनांक 21.01.2022 द्वारा श्री हक की निलंबन अवधि को दिनांक 29.01.2022 के आगे 120 (एक सौ बीस) दिनों तक अर्थात् दिनांक 29.05.2022 तक विस्तारित किया गया।

5. और चूँकि बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में श्री हक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी और इसके निमित्त विभागीय ज्ञापन सं०-8825 दिनांक 03.11.2021 के माध्यम से आरोप पत्र निर्गत किया गया। श्री हक द्वारा उक्त आरोप पत्र के आलोक में बचाव बयान समर्पित करने हेतु पत्र दिनांक 25.11.2021 के माध्यम से अतिरिक्त कागजात की मांग की गयी। श्री हक के उक्त पत्र के आलोक में बिहार पुलिस मुख्यालय से मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। इसी बीच श्री हक द्वारा पत्र दिनांक 17.12.2021 के माध्यम से बचाव-बयान समर्पित किया गया। श्री हक के पत्र दिनांक 25.11.2021 के आलोक में पुलिस मुख्यालय द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया, जिससे श्री हक को अवगत कराते हुए बचाव-बयान के अतिरिक्त कुछ कहना हो तो, 7 (सात) दिनों के अंदर समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में श्री हक द्वारा पत्र दिनांक 21.01.2022 के माध्यम से अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री हक के बचाव-बयान पर बिहार पुलिस मुख्यालय से मंतव्य हेतु अनुरोध किया गया। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा पत्र दिनांक 24.03.2022 के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

श्री हक द्वारा बचाव-बयान में अपने विरुद्ध गठित आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया। उनके द्वारा समर्पित बचाव-बयान की समीक्षा पुलिस मुख्यालय के मंतव्य एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि उनके द्वारा समर्पित बचाव-बयान में कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया गया, जिससे उनके विरुद्ध गठित आरोपों की स्थिति में परिवर्तन हो सके। फलस्वरूप उनके विरुद्ध गठित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं० 4377, दिनांक 04.05.2022 के माध्यम से मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री हक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में सुनवाई की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, ऐसी स्थिति में श्री मो० शफीउल हक, भा०पु०से० (2007) के निलंबन को बनाये रखने के औचित्य/आधार के संबंध में निलंबन समीक्षा समिति द्वारा विचार किया गया तथा विचारोपरांत समिति द्वारा श्री हक के निलंबन को दिनांक 29.05.2022 के आगे 180 (एक सौ अस्सी) दिनों तक अर्थात् दिनांक 25.11.2022 तक विस्तारित करने की अनुशंसा की गयी, जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया गया।

6. अतः अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(8)(d) के तहत श्री मो० शफीउल हक, भा०पु०से० (2007) के निलंबन अवधि दिनांक 29.05.2022 के आगे 180 (एक सौ अस्सी) दिनों तक अर्थात् दिनांक 25.11.2022 तक विस्तारित की जाती है।

7. मो० शफीउल हक, भा०पु०से० (2007) को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० संधिल कुमार, सचिव।

सं० 1/एम०2-60-15/2021 गृ०आ०-7051

15 जुलाई 2022

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के जाँच प्रतिवेदन एवं उसमें निहित निष्कर्ष तथा पुलिस महानिदेशक, बिहार की अनुशंसा के आलोक में औरंगाबाद जिला में बालू के अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, इसमें संलग्न लोगों को मदद पहुँचाने, अवैध उत्खनन/परिवहन में संलिप्त रहने, अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखने एवं संदिग्ध आचरण से संबंधित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(1)(a) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुधीर कुमार पोरिका, भा०पु०से० (2010), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद को विभागीय संकल्प 5103, दिनांक 27.07.2021 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। साथ ही, उक्त गंभीर आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित करने के निमित्त विभागीय ज्ञापन 6292, दिनांक 24.08.2021 द्वारा "आर्टिकल्स ऑफ चार्ज", "स्टेटमेंट ऑफ इम्यूटेशन ऑफ मिसबिहेवियर एण्ड मिसकण्डक्ट" एवं साक्ष्य/गवाह तालिका सहित निर्गत किया गया।

2. और चूँकि अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(1)(i), जिसके तहत श्री पोरिका को निलंबित किया गया, के प्रावधानों के आलोक में श्री पोरिका के निलंबन की संपुष्टि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक 26011/25/2021.जैप्प, दिनांक 06.08.2021 के फलस्वरूप श्री पोरिका के निलंबन की अवधि 60 (साठ) दिनों तक अर्थात् दिनांक 27.07.2021 से 24.09.2021 तक बरकरार थी। श्री पोरिका के निलंबन अवधि की समीक्षा हेतु दिनांक 13.09.2021 को आयोजित निलंबन समीक्षा समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में विभागीय संकल्प सं० 7269, दिनांक 20.09.2021 द्वारा दिनांक 24.09.2021 के आगे 120 दिनों तक अर्थात् दिनांक 22.01.2022 तक निलंबन अवधि को विस्तारित किया गया। पुनः दिनांक 07.01.2022 को आयोजित निलंबन समीक्षा समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में विभागीय संकल्प सं० 551, दिनांक 21.01.2022 द्वारा श्री पोरिका के निलंबन अवधि को दिनांक 22.01.2022 के आगे 180 दिनों तक अर्थात् दिनांक 21.07.2022 तक विस्तारित किया गया।

3. और चूँकि श्री पोरिका के विरुद्ध उक्त गंभीर आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया। इसके निमित्त विभागीय ज्ञापन सं० 6292, दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से "आर्टिकल्स ऑफ चार्ज" एवं "स्टेटमेंट ऑफ इम्यूटेशन ऑफ मिसबिहेवियर एण्ड मिसकण्डक्ट" साक्ष्य/गवाह तालिका सहित निर्गत करते हुए अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 8(5)(i) के तहत 30 दिनों के अंदर बचाव-बयान समर्पित करने हेतु श्री पोरिका को अवसर प्रदान किया गया। उक्त के आलोक में श्री पोरिका द्वारा बचाव-बयान समर्पित किया गया। श्री पोरिका द्वारा समर्पित बचाव-बयान की समीक्षोपरांत उनका बचाव-बयान संतोषप्रद नहीं पाया गया। फलस्वरूप उनके विरुद्ध ज्ञापन दिनांक 24.08.2021 द्वारा गठित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं० 40,

दिनांक 04.01.2022 के माध्यम से मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। मामले में मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार के समक्ष सुनवाई प्रक्रियाधीन है। आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना से श्री सुधीर कुमार पोरिका, भा0पु0से0 (2010) के विरुद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन संबंधी जाँच भी प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस जाँच के फलाफल की सूचना अप्राप्त है।

4. अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(1b) के तहत भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए निलंबित श्री पोरिका को दो वर्ष तक राज्य निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा पर निलंबन में बनाये रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में श्री पोरिका के निलंबन को बनाये रखने के औचित्य/आधार के संबंध में दिनांक 01.07.2022 को निलंबन समीक्षा समिति द्वारा विचार किया गया। विचारोपरांत समिति द्वारा श्री पोरिका के निलंबन अवधि को दिनांक 21.07.2022 के आगे 180 दिनों तक अर्थात् दिनांक 17.01.2023 तक विस्तारित करने की अनुशंसा की गयी, जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

5. अतः अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(8)(क) के प्रावधानों के अंतर्गत श्री सुधीर कुमार पोरिका, भा0पु0से0 (2010) के निलंबन की अवधि दिनांक 21.07.2022 के आगे 180 दिनों तक अर्थात् दिनांक 17.01.2023 तक विस्तारित किया जाता है।

6. श्री सुधीर कुमार पोरिका, भा0पु0से0 (2010) को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

सं0 1/एम02-60-15/2021 गृ0आ0-550

21 जनवरी 2022

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के जाँच प्रतिवेदन एवं उसमें निहित निष्कर्ष तथा पुलिस महानिदेशक, बिहार की अनुशंसा के आलोक में भोजपुर जिला में बालू के अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, इसमें संलग्न लोगों को मदद पहुँचाने, अवैध उत्खनन/परिवहन में संलिप्त रहने, अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखने एवं संदिग्ध आचरण से संबंधित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(1)(a) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राकेश कुमार दूबे, भा0पु0से0 (नवप्रोन्नत), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, भोजपुर को विभागीय संकल्प 5102, दिनांक 27.07.2021 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। साथ ही, उक्त गंभीर आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित करने के निमित्त विभागीय ज्ञापन 6293, दिनांक 24.08.2021 द्वारा “आर्टिकल्स ऑफ चार्ज”, “स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेन्स ऑफ मिसबिहेवियर एण्ड मिसकण्डक्ट”, साक्ष्य/गवाह तालिका सहित निर्गत किया गया।

2. और चूँकि अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के अंतर्गत विहित प्रक्रिया के आलोक में श्री दूबे के निलंबन के संबंध में अपेक्षित प्रतिवेदन गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजते हुए उनके निलंबन को संपुष्ट करने हेतु विभागीय पत्रांक 5202, दिनांक 28.07.2021 के माध्यम से अनुरोध किया गया।

3. और चूँकि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक 26011/24/2021-IPS.II, दिनांक 06.08.2021 के माध्यम से श्री दूबे के निलंबन अवधि को दिनांक 24.09.2021 तक संपुष्ट की गयी।

4. और चूँकि अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(8)(a) के अद्यतन प्रावधान के अनुसार निलंबन, विस्तारण के पूर्व 60 दिनों तक वैध रहता है और इसका विस्तारण पहली बार अधिकतम 120 दिनों के लिए किया जा सकता है। भारत सरकार के संदर्भित पत्र के आलोक में श्री दूबे के निलंबन की अवधि 60 (साठ) दिनों तक अर्थात् दिनांक 27.07.2021 से 24.09.2021 तक थी। श्री दूबे के निलंबन अवधि को उक्त नियमावली के नियम 3(8)(a) के आलोक में दिनांक 24.09.2021 के आगे 120 दिनों तक अर्थात् दिनांक 22.01.2022 तक विस्तारित करने की अनुशंसा निलंबन समीक्षा समिति द्वारा की गयी। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प सं0 7268, दिनांक 20.09.2021 द्वारा श्री दूबे की निलंबन अवधि को दिनांक 24.09.2021 के आगे 120 दिनों तक अर्थात् दिनांक 22.01.2022 तक विस्तारित किया गया।

5. और चूँकि श्री दूबे के विरुद्ध उक्त गंभीर आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित है और इसके निमित्त विभागीय ज्ञापन सं0 6293, दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से “आर्टिकल्स ऑफ चार्ज” एवं “स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेन्स ऑफ मिसबिहेवियर एण्ड मिसकण्डक्ट” साक्ष्य/गवाह तालिका सहित निर्गत करते हुए अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 8(5)(a) के तहत 30 दिनों के अंदर बचाव-बयान समर्पित करने हेतु श्री दूबे को अवसर प्रदान किया गया। उक्त के आलोक में श्री दूबे द्वारा बचाव-बयान समर्पित करने हेतु पत्र दिनांक 11.09.2021 द्वारा अतिरिक्त कागजात की माँग की गयी। इस संबंध में उन्हें यह बताया जाने पर कि आरोप पत्र के साथ उपलब्ध कराये गये साक्ष्य/कागजात बचाव-बयान समर्पित करने के लिए पर्याप्त हैं, उनके द्वारा पुनः उन्हीं कागजात की आवश्यकता बतलाते हुए पत्र दिनांक 21.10.2021 के माध्यम से माँग की गयी। श्री दूबे के उक्त पत्रों के संदर्भ में बिहार पुलिस मुख्यालय के मंतव्य से उन्हें अवगत कराया गया कि उनके द्वारा याचित अतिरिक्त कागजात आरोपों के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है और आरोप पत्र के साथ सभी आवश्यक कागजात उपलब्ध करा दिये गये हैं, जो बचाव-बयान समर्पित करने के लिए पर्याप्त हैं। साथ ही, उनको बचाव-बयान समर्पित करने का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 10 दिनों का समय प्रदान किया गया। उक्त समयावधि बीत

जाने के बाद भी उनके द्वारा बचाव-बयान समर्पित नहीं किया गया। श्री दूबे के उक्त व्यवहार से प्रतीत होता है कि बचाव-बयान ससमय समर्पित करने में उनकी कोई रुची नहीं है और इस विभागीय कार्यवाही को विलंबित करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है।

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार श्री राकेश कुमार दूबे, भा0पु0से0 (नवप्रोन्नत) के विरुद्ध आय के ज्ञात एवं वैध स्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियाँ अर्जित करने के संबंध में आर्थिक अपराध इकाई, थाना कांड सं0 17/2021, दिनांक 15.09.2021 दर्ज किया गया है। उक्त थाना कांड अनुसंधानान्तर्गत है। ऐसी स्थिति में श्री दूबे के निलंबन को बनाये रखने के औचित्य/आधार के संबंध में दिनांक 07.01.2022 को निलंबन समीक्षा समिति द्वारा विचार किया गया। विचारोपरांत समिति द्वारा श्री दूबे के निलंबन अवधि को दिनांक 22.01.2022 के आगे 180 दिनों तक अर्थात् दिनांक 21.07.2022 तक विस्तारित करने की अनुशंसा की गयी, जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

6. अतः अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(8)(d) के प्रावधानों के अंतर्गत श्री राकेश कुमार दूबे, भा0पु0से0 (नवप्रोन्नत) के निलंबन की अवधि दिनांक 22.01.2022 के आगे 180 दिनों तक अर्थात् दिनांक 21.07.2022 तक विस्तारित की जाती है।

7. श्री राकेश कुमार दूबे, भा0पु0से0 (नवप्रोन्नत) को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के0 संधिल कुमार, सचिव।

सं0 1/एम02-60-15/2021 गृ0आ0-551

21 जनवरी 2022

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के जाँच प्रतिवेदन एवं उसमें निहित निष्कर्ष तथा पुलिस महानिदेशक, बिहार की अनुशंसा के आलोक में औरंगाबाद जिला में बालू के अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, इसमें संलग्न लोगों को मदद पहुँचाने, अवैध उत्खनन/परिवहन में संलिप्त रहने, अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखने एवं संदिग्ध आचरण से संबंधित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(1)(a) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुधीर कुमार पोरिका, भा0पु0से0 (2010), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद को विभागीय संकल्प 5103, दिनांक 27.07.2021 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। साथ ही, उक्त गंभीर आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित करने के निमित्त विभागीय ज्ञापन 6292, दिनांक 24.08.2021 द्वारा "आर्टिकल्स ऑफ चार्ज", "स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेणन्स ऑफ मिसबिहेवियर एण्ड मिसकण्डक्ट" एवं साक्ष्य/गवाह तालिका सहित निर्गत किया गया।

2. और चूँकि अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के अंतर्गत विहित प्रक्रिया के आलोक में श्री पोरिका के निलंबन के संबंध में अपेक्षित प्रतिवेदन गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजते हुए उनके निलंबन को संपुष्ट करने हेतु विभागीय पत्रांक 5202, दिनांक 28.07.2021 के माध्यम से अनुरोध किया गया।

3. और चूँकि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक 26011/25/2021-IPS.II, दिनांक 06.08.2021 के माध्यम से श्री पोरिका के निलंबन अवधि को दिनांक 24.09.2021 तक संपुष्ट की गयी।

4. और चूँकि अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(8)(a) के अद्यतन प्रावधान के अनुसार निलम्बन, विस्तारण के पूर्व 60 दिनों तक वैध रहता है और इसका विस्तारण पहली बार अधिकतम 120 दिनों के लिए किया जा सकता है। भारत सरकार के संदर्भित पत्र के आलोक में श्री पोरिका के निलंबन की अवधि 60 (साठ) दिनों तक अर्थात् दिनांक 27.07.2021 से 24.09.2021 तक थी। श्री पोरिका के निलंबन अवधि को उक्त नियमावली के नियम 3(8)(a) के आलोक में दिनांक 24.09.2021 के आगे 120 दिनों तक अर्थात् दिनांक 22.01.2022 तक विस्तारित करने की अनुशंसा निलंबन समीक्षा समिति द्वारा की गयी। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प सं0 7269, दिनांक 20.09.2021 द्वारा श्री पोरिका की निलंबन अवधि को दिनांक 24.09.2021 के आगे 120 दिनों तक अर्थात् दिनांक 22.01.2022 तक विस्तारित किया गया।

5. और चूँकि श्री पोरिका के विरुद्ध उक्त गंभीर आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित है और इसके निमित्त विभागीय ज्ञापन सं0 6292, दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से "आर्टिकल्स ऑफ चार्ज" एवं "स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेणन्स ऑफ मिसबिहेवियर एण्ड मिसकण्डक्ट" साक्ष्य/गवाह तालिका सहित निर्गत करते हुए अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 8(5)(a) के तहत 30 दिनों के अंदर बचाव-बयान समर्पित करने हेतु श्री पोरिका को अवसर प्रदान किया गया। उक्त के आलोक में श्री पोरिका द्वारा बचाव-बयान समर्पित किया गया। श्री पोरिका द्वारा समर्पित बचाव-बयान की समीक्षोपरांत उनका बचाव-बयान संतोषप्रद नहीं पाया गया। फलस्वरूप उनके विरुद्ध ज्ञापन दिनांक 24.08.2021 द्वारा गठित आरोपों की जाँच हेतु मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना से श्री पोरिका के विरुद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन संबंधी जाँच भी प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया है। ऐसी स्थिति में श्री पोरिका के निलंबन को बनाये रखने के औचित्य/आधार के संबंध में दिनांक 07.01.2022 को निलंबन समीक्षा समिति द्वारा विचार किया गया तथा विचारोपरांत समिति द्वारा श्री पोरिका के निलंबन को दिनांक 22.01.2022 के आगे 180 दिनों तक अर्थात् दिनांक 21.07.2022 तक विस्तारित करने की अनुशंसा की गयी, जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

6. अतः अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुषासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(8)(d) प्रावधानों के अंतर्गत श्री सुधीर कुमार पोरिका, भा0पु0से0 (2010) के निलंबन की अवधि दिनांक 22.01.2022 के आगे 180 दिनों तक अर्थात् दिनांक 21.07.2022 तक विस्तारित की जाती है।

7. श्री सुधीर कुमार पोरिका, भा0पु0से0 (2010) को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>